



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272164  
CG-DL-E-29042026-272164

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2063]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2063]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

**का.आ. 2136(अ).**— कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) तारीख 24 जून 2025, द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की असाधारण अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2839(अ), तारीख 24 जून 2025 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में और ऐसी भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) में के या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विलंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिला राँची, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए सहमत है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि 1338.57 एकड़ (लगभग) या 541.71 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उसपर के सभी अधिकार तारीख 24 जून 2025 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के सिवाय, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थातः -

- i. सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, क्षतियों, इत्यादि और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदाय करेगी;
- ii. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जायेगा जिसमें शर्त (i) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और वैसे ही इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में जैसे अपीलों आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
- iii. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
- iv. सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने की शक्ति नहीं होगी; और
- v. सरकारी कंपनी, ऐसे निर्देशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/6/2021-एलएआईआर]

डॉ. माणिक चंद्र पंडित, आर्थिक सलाहकार

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

**S.O. 2136(E).**— Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2839 (E), dated the 24<sup>th</sup> June, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 24<sup>th</sup> June, 2025, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Central Coalfields Limited, Ranchi, Jharkhand (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 1338.57 acres (approximately) or 541.71 hectares (approximately) and all rights in or over the said land so vested, shall with effect from 24<sup>th</sup> June 2025, instead of

continuing to so vest in the Central Government shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (i) the Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
- (ii) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (i) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land so vested, shall also be borne by the Government company;
- (iii) the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in or over the said land so vested;
- (iv) the Government company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
- (v) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F. No. 43015/6/2021-LAIR]

Dr. MANIK CHANDRA PANDIT, Economic Adviser